पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख–पत्र

वर्ष 21, अंक 4/2020

'ग्रीन एक्शन वीक' 2020 अभियान

राष्ट्रीय स्तर पर परिचर्चा आयोजित

'ग्रीन एक्शन वीक' प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाने वाला एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जो सतत् उपभोग को बढ़ावा देने का आमजन से आह्वान करता है। यह अभियान स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जर्वेशन की एक पहल है, जिसकी शुरूआत 1990 में स्वीडन में हुई और 2010 तक यह एक अन्तर्राष्ट्रीय अभियान के रूप में स्थापित हो गया। इस अभियान में वर्तमान में 35 देशों की करीब 65 संस्थाएं भाग लेती हैं, जिनमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के देश शामिल हैं।

जयपुर स्थित अग्रणी उपभोक्ता संस्था 'कट्स' द्वारा भारत में 'ग्रीन एक्शन वीक' अभियान संचालित किया जा रहा है। 'ग्रीन एक्शन वीक' 2020 अभियान का इस वर्ष का विषय शेयरिंग कम्यूनिटी है, जिसके अन्तर्गत समुदाय के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं की सामूहिक साझेदारी–सहयोग की भावना को बढ़ावा देना प्रमुख है। साथ ही सतत् उपभोग की कल्पना को भी साकार करने का संकल्प इस अभियान का एक अंग है।

इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर के अभियान में 'कट्स' ने दस राज्यों में ग्यारह विभिन्न संस्थाओं के साथ भागीदारी की, जिनमें असम की 'एनवाईरोन', छत्तीसगढ़ की 'सहभागी समाज सेवी संस्था', दिल्ली की 'एनवायरमेंट एण्ड

सोशल रिसर्च ओर्गेनाईजेशन', कर्नाटक की 'सेंटर फॉर डवलपमेंट एण्ड एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन', केरल की 'श्याम शिक्षण प्रयोग', मध्यप्रदेश की 'सिकोइडिकोन', ओडिशा की 'जीवन रेखा परिषद्' और 'यूथ फॉर सोशल डवलपमेंट', तमिलनाडू की 'पीस ट्रस्ट', उत्तराखण्ड की 'रूरल लिटिगेशन एण्ड एनटाईटलमेंट केन्द्र' और उत्तर प्रदेश की 'शोहरतगढ़ एनवायरमेंट सोसायटी' थी।

सभी संस्थाओं द्वारा अपने–अपने राज्यों में अभियान की थीम पर आधारित कार्यशालाऐं, सहभागी परिचर्चाएं, टॉक शो, जागरूकता कार्यक्रम जैसे कैम्पों का आयोजन, हस्ताक्षर अभियान व विभिन्न विषय सम्बन्धित शिक्षा व संचरण हेतु पाठनीय सामग्री का प्रकाशन और वितरण किया गया।

उपरोक्त गतिविधियों का सम्पूर्ण ब्यौरा और लेखाजोखा पर चर्चा करने के लिए जयपुर में इस राष्ट्रीय परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संस्था प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी देते हुए, उनके द्वारा अपने–अपने राज्यों में की गई गतिविधियों और उनसे प्राप्त उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण किया।

परिचर्चा प्रारम्भ करते हुए 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने इस अभियान पर प्रकाश डालते हुए सतत् उपभोग को बढ़ावा देने के लिए विश्वस्तर पर आयोजित इस अभियान की विशेषताएं बताई। उन्होंने कहा कि भारत में इस अभियान की शुरूआत राजस्थान में वर्ष 2011 से की गई थी। इस अभियान की थीम पिछले कुछ वर्षों से 'शेयरिंग कम्यूनिटी' है। चेरियन ने कहा कि सभी गतिविधियों से समाज में यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग किया जाए जिससे सतत् उपभोग को बढ़ावा मिल सके।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में 'कट्स' के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी अमरदीप सिंह ने 'ग्रीन एक्शन वीक इंडिया'2020 अभियान के बारे में जानकारी दी। सिंह ने 'ग्रीन एक्शन वीक' के तहत पिछले वर्षों के अनुभव और गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए अभियान के विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में बताया।

इसी क्रम में कार्यक्रम के आगामी सत्रों में दस राज्यों की ग्यारह संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उनके द्वारा किए गये विभिन्न आयोजनों का ब्यौरा दिया, जिनका समापन राज्य स्तरीय परिचर्चाओं के साथ हुआ। राजस्थान की 'ग्रीन एक्शन वीक' गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण निमिषा शर्मा द्वारा दिया गया।

इस अंक में...

- बेनामी लोग खा गए गरीबों का राशन 4
- सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के प्रयास 6
- हटेगी धुंध, खिलेगी आर्थिक विकास की धूप .. 7
- जलाशयों को शुद्ध करेगा 'पिंजरा' 9
- दोगुनी हुई 'सिर्फ बेटी' की ख्वाहिश 10

किचन गार्डन में उगाई सब्जियां व फल स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण-'कट्स'

स्वस्थ जीवन के लिए जैविक खाद्य पदार्थ अति आवश्यक है। जैविक खाद्य पदार्थ जैविक खेती से प्राप्त होते हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए समय समय पर 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजर्वेशन के आर्थिक सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के तहत रसायन युक्त जहरीली सब्जियों एवं फलों से बचने का सन्देश दिया जाता है तथा जन समुदाय को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जाता है। महिलाओं को घरों में किचन गार्डन विकसित करने की भी प्रेरणा दी जाती है।

'कट्स' द्वारा जयपुर स्थित विकासोन्मुख संस्थान, नरेना के सहयोग से वार्ड नंबर 80 व 96 (ग्रेटर) अयोध्या नगर, गोपालपुरा बाईपास व मदरामपुरा, सांगानेर, क्षेत्र की महिलाओं के साथ ग्रीन एक्शन वीक 2020 के तहत किचन गार्डनिंग की गतिविधियां आयोजित की गई थीं। जिसका फॉलोअप मीटिंग के तहत घर-घर जाकर सत्यापन किया गया। कार्यक्रम में किसान कॉल सेंटर से आए अमित शर्मा ने महिलाओं को किचन गार्डन में सब्जियां लगाने में आने वाली परेशानियों एवं रोग से बचाव आदि की जानकारी दी।

संस्थान सचिव राजेश मालाकार ने बताया कि यह गतिविधियां सतत् प्रक्रिया का हिस्सा है। इन दोनों क्षेत्रों की महिलाओं की समस्याओं के निदान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर निरंतर समाधान किया जाएगा। विजिट के दौरान 'कट्स' के राजदीप पारीक, आराधना गुप्ता एवं कार्यक्रम समन्वयक शारदा सैनी भी मौजूद थे।

किसानों की आय दोगुनी करने का तरीका है जैविक खेती

देश में अब गुणवत्ता आधारित फसलों की मांग बढ़ रही है। जैविक खेती इसका एकमात्र विकल्प है। जैविक खेती किसानों की आय दोगुनी करने का सबसे अच्छा तरीका है। किसान रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों पर निर्भरता कम करें। क्योंकि, इनके उपयोग से कृषि भूमि की उर्वरता खत्म हो रही है। 'कट्स' द्वारा स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजर्वेशन के सहयोग से एवं रामकृष्ण शिक्षण संस्था के तत्वावधान में कोटा जिले के भदाना गांव में आयोजित लाड़पुरा ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में यह सब उभरकर सामने आया।

कार्यशाला में कृषि विभाग के उप निदेशक शंकरलाल मीणा ने कहा कि रासायनिक खादों से कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही है। किसानों को अपने खेत की मृदा की जांच करानी चाहिए। इससे पता लगेगा कि मिट्टी में किन तत्वों की कमी है। कृषि विशेषज्ञ दीन दयाल ने कहा कि पारंपरिक खेती से ही किसानों और समाज का भला हो सकेगा। कार्यक्रम का संचालन करते हुए पर्यावरणविद् बृजेश विजयवर्गीय ने बताया कि महामारी के बाद जैविक उत्पादनों की मांग बढ़ी है। हमें जैविक खाद की उपयोगिता को समझना होगा। इससे उन्नत उत्पाद तैयार होंगे, जो किसानों के लिए घाटे का सौदा कतई नहीं हो सकते। कृषि पर्यवेक्षक राकेश सुमन ने घरों में किचन गार्डन लगाकर जैविक उत्पादों की खेती करने के बारे मे बताया।

कार्यशाला के प्रारंभ में 'कट्स' के परियोजना अधिकारी राजदीप पारीक ने जैविक खेती के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यशाला में किसानों और कृषि क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कोरोना गाइड लाइन की पालना करते हुए सक्रिय रूप से भाग लिया।

मुनाफा कमा गई पेट्रोलियम कंपनियां

आम आदमी को राहत का लॉलीपॉप देकर सरकार ने 2017 से प्रतिदिन पेट्रोल-डीजल के दाम तय करने का फैसला लिया था। इसके बाद क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों पर दाम रोज तय होने लगे, लेकिन इससे आम आदमी को राहत नहीं मिली। तेल कंपनियां और सरकारें इन पर टैक्स बढ़ाकर मालामाल हो गई।

केंद्र सरकार ने क्रूड ऑयल के घटते दामों का फायदा आम आदमी को देने के बजाय अपने मुनाफे के लिए उपयोग टैक्स बढ़ाकर किया। केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकारें भी टैक्स में कोई राहत नहीं दे रही। दूसरी तरफ तीन प्रमुख तेल कंपनियों की पांचों अंगुलियां घी में है। पेट्रोलियम कंपनियों का मुनाफा सितंबर 2020 की तिमाही में करीब 11 हजार करोड़ रुपए रहा। राजस्थान सरकार की कमाई भी पिछले साल की तुलना में 1100 करोड़ ज्यादा रही और स्टेट टैक्स से 8379 करोड़ रुपए मिले। *(रा.प., 22.12.20)*

पौधों में पानी नहीं, बनते रहे बिल

पार्कों और हरियाली के रख-रखाव के नाम पर जेडीए में बरसों से गोलमाल हो रहा है। बिना जरूरत के पौधों में पानी डाला गया और पौधों की छंटाई के नाम पर भी खानापूर्ति ही की गई। इतना ही नहीं ठेकेदारों ने उद्यान शाखा के अधिकारियों से मिलकर पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों रुपए के फर्जी बिल उठाकर जेडीए को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है।

यही वजह है कि पिछले एक साल में पार्कों को बेहतर बनाने का बजट आधा ही रह गया। सूत्रों के अनुसार अब तक बिना किसी सिस्टम के ही टैंकरों से पानी डाला गया। ठेकेदार सीधे आकर उद्यान शाखा में बिल पेश करते थे और खुद ही टैंकरों की संख्या बताते थे और उसी के अनुसार भुगतान हो रहा था। *(रा.प., 17.10.20)*

हकदार किसानों को नहीं मिला लाभ

प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ करीब तीन लाख से ज्यादा गरीब किसानों को नहीं मिल पाया है। योजना के तहत वास्तविक रूप से पात्र होने के बावजूद ये किसान प्रशासन की उदासीनता के चलते आर्थिक सम्बल को तरस रहे हैं।

जबकि 63 हजार 936 किसानों ने करदाता होने के बावजूद इस योजना के तहत गैरवाजिब तरीकों से करीब 57 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि उठा ली। इन अपात्रों पर मेहरबानी इस कदर है कि उनसे अब तक नाम मात्र की भी वसूली नहीं हो पाई है। *(रा.प., 01.11.20)*

निर्भया फंडः कुंडली मारे बैठी सरकारें

उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में बेटियों से बलात्कार की घटनाओं पर हाहाकार मचा है। वहीं निर्भया कांड के बाद 2015 में शुरू निर्भया फंड पर यूपी, राजस्थान तथा मध्यप्रदेश समेत कई सरकारें कुंडली मारकर बैठी हैं। कुछ राज्यों में फंड की 40 फीसदी राशि भी खर्च नहीं हुई है।

साल-दर-साल राज्यों के पास बिना खर्च की राशि बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार का भी इस ओर ध्यान नहीं है। जबकि निर्भया कांड के बाद देश में बेटियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके बावजूद बेटियों के साथ बलात्कार, हत्या, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। यदि वन स्टॉप सेंटर, महिला हैल्प लाइन और महिला पुलिस स्वयंसेवक जैसे काम हो जाते तो बेटियां ज्यादा सुरक्षित होतीं, लेकिन हकीकत में किसी भी राज्य में अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। *(रा.प., 03.10.20)*

किसानों को बिजली बिल पर राहत खत्म

राज्य में 13 लाख किसानों को डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के रूप में मिल रही राहत सियासत की भेंट चढ़ गई है। किसानों के बिजली बिलों में डीबीटी की यह व्यवस्था पिछली भाजपा सरकार ने शुरू की थी। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने इसे पहले तो अघोषित रूप से बंद कर दिया। अब परीक्षण के नाम पर 'रोक' लगा दी है।

ऊर्जा सचिव की मौखिक मुहर के बाद अब केवल बिजली कंपनियों की समन्वय समिति की मुहर लगने की औपचारिकता बाकी है। भाजपा सरकार ने हर कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में 833 रुपए प्रति माह सब्सिडी देना तय किया था इससे सालाना लगभग 1000 करोड़ का भार आ रहा था। किसानों को 688 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। *(रा.प., 23.12.20)*

निःशुल्क दवा योजना की करोड़ों रुपए की दवाएं बर्बाद

राजस्थान में कोरोना का एक और बड़ा साइड इफेक्ट सामने आया है। कोरोना के कारण सामान्य बीमारियों के मरीज सरकारी अस्पतालों और औषधि भंडारों में पहुंचे ही नहीं। इस कारण मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत प्रदेश भर में भेजी गई 75 लाख 77 हजार रुपए की दवाएं अक्टूबर में एक्सपायर हो गईं। नवंबर में भी करीब दो करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं बर्बाद होने के कगार पर हैं।

दवाओं की एक्सपायरी को लेकर प्रदेश के सभी सीएमएचओ व पीएमओ से स्पष्ट कारण बताने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार जानना चाहती कि ऐसे क्या कारण रहे कि इतनी मात्रा में दवाएं एक्सपायर हो गईं। दवाओं की एक्सपायरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। *(दै.भा., 13.11.20)*

पानी के सैंपल की जांच में घालमेल

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आला अधिकारियों व निजी लैब संचालकों द्वारा पेयजल सैंपलों के नाम पर 20 करोड़ रुपए का घालमेल सामने आया है। प्रदेश में 233 ब्लॉकों में बिल उठाने से पहले यह मामला उजागर होने से विभाग ने भुगतान रोक दिया है और उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है।

निजी लैब संचालकों ने पानी के सैंपल जांचे बिना ही 7 करोड़ से ज्यादा का भुगतान उठाने की तैयारी कर ली। लेकिन पेयजल जांच के लिए दूसरे टेंडर ने अफसरों और लैब संचालकों की मिलीभगत की पोल खोल दी। *(रा.प., 03.12.20)*

बेनामी लोग खा गए गरीबों का राशन

जयपुर जिले में एक लाख बेनामी लोग पिछले 5 साल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का 54 करोड़ रुपए का राशन का गेहूं खा गए। इन बेनामी लोगों का पता तब चला जब वन नेशन-वन राशन कार्ड के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों के सभी सदस्यों का आधार नंबर योजना में लिंक करना शुरू हुआ।

आधार नंबर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जोड़ने के लिए राशन का गेहूं लेने वाले परिवारों के सदस्यों से आधार कार्ड की फोटो कॉपी मांगी गई। दो माह के बाद भी आधार कार्ड उपलब्ध नहीं कराने के कारण जिले में एक लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया गया। इस योजना के तहत 5 किलो अनाज हर माह प्रति व्यक्ति दिया जाता है।

गौरतलब है कि इस योजना में जिन्हें गेहूं मिलता था, उन्हें भामाशाह योजना से मिलने वाले स्वास्थ्य बीमा योजना का भी लाभ मिलता था। जिसमें 3 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। ऐसा होने से सरकार को दोहरा नुकसान हुआ है। अधिकारी दबी जबान में स्वीकारते हैं कि अयोग्य लोगों के इलाज के लिए करीब 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का स्वास्थ्य बीमा भुगतान किया है। *(दै.भा., 16.12.20)*

'किराए की छत' पर सियासत हावी

कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के पलायन से सकते में आई केंद्र सरकार ऐसे लोगों को किराए की छत मुहैया कराने में जुटी है। लेकिन उसके इन प्रयासों को धक्का लगा है। केंद्र ने जो योजना बनाई, उसे कांग्रेस शासित राज्यों ने अपनाया ही नहीं। राजस्थान सहित कांग्रेस शासित किसी अन्य राज्य ने योजना को लागू भी किया, तो बाद में उसे ठण्डे बस्ते में डाल दिया। अब केंद्र ने फिर दोहराया है कि राज्य इस पर गंभीरता से काम करें।

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को किराए (रेडी टू मूव आवास) पर देने के लिए खाली आवास चिन्हित करने के लिए कहा था। ज्यादातर कांग्रेस शासित राज्यों ने इसे दरकिनार कर दिया या लागू करने के बाद आगे नहीं बढ़ाया। राजस्थान में भी इस स्कीम को अपनाने के बाद ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है। *(रा.प., 18.12.20)*

अफसरों ने डुबोए 53 करोड़ रुपए

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ में बेहतरीन काम करने का दावा करने वाली राजस्थान सरकार ही इस योजना को आगे बढ़ाने में नाकाम रही। हालात यह है कि योजना में मैचिंग ग्रांट खर्च नहीं कर पाने के कारण केंद्र की ओर से दिए जाने वाले 53 करोड़ रुपए से राज्य सरकार हाथ धो बैठी।

महिला एवं समाज कल्याण मंत्री ममता भूपेश खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में महज 28 हजार रुपए खर्च कर पाई, जब कि जिले के लिए 50 लाख रुपए का सालाना बजट है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव का इस मामले में कहना है कि केंद्र से जिलों को दी जाने वाली राशि की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर होनी चाहिए। जिला कलेक्टर आवश्यकता अनुसार रुपए खर्च करते हैं। जहां विलंब किया गया है, उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

(रा.प., 12.10.20)

मिलीभगत से सरकार को लगाई चपत

झुंझनूं जिला मुख्यालय स्थित उप पंजीयन कार्यालय में करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है। यहां जान बूझकर सरकार को चपत लगाई जा रही है। पंजीयन और मुद्रांक विभाग अजमेर की उप महानिरीक्षक (प्रवर्तन) चंदना खोरवाल द्वारा की गई जांच में यह सच सामने आया कि वर्ष 2015 से जून 2020 के बीच राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया।

खोरवाल ने जांच में दो करोड़ 79 लाख रुपए की करवंचना पकड़ी है। यह गड़बड़ी 116 रजिस्ट्री की जांच में मिली है। यह राशि वसूली योग्य मानी गई है। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही मानी गई।

(रा.प., 04.10.20)

किए जा रहे हैं अमूल्य कॉर्निया नष्ट

नेत्रदान कार्यक्रम के तहत आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान को मिले अमूल्य कॉर्निया को बड़ी संख्या में नष्ट किया जा रहा है। सोसायटी से मिले आंकड़ों के अनुसार दान में जितने कॉर्निया मिले उससे काफी कम ट्रांसप्लांट किए गए। राजस्थान में वर्ष 2018 से मार्च 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार 1197 कॉर्निया अनफिट व संक्रमित मानकर नष्ट कर दिए गए। जबकि 2619 कॉर्निया ट्रांसप्लांट किए गए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रांसप्लांट नहीं किए जाने योग्य कॉर्निया को शोध में काम लिया जा सकता है। आई बैंक सोसायटी लोगों को नेत्रदान कार्यक्रम का महत्व बताकर एसएमएस में 70 प्रतिशत कॉर्निया दान करवा रही है। स्वैच्छिक नेत्रदान 30 प्रतिशत है। एसएमएस में यह निशुल्क है। जबकि निजी अस्पतालों में कॉर्निया के 6 हजार रुपए और ट्रांसप्लांटेशन में 20 से 25 हजार रुपए तक वसूले जाते हैं। *(रा.प., 03.10.20)*

भारतीयों ने उधार लेकर चलाई गृहस्थी

एक शोध में खुलासा हुआ है कि कोरोना काल में 46 फीसदी भारतीयों ने अपनी गृहस्थी चलाने के लिए उधार का सहारा लिया। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर चार में से एक व्यक्ति ने अपने दोस्त या परिवार वालों से उधार लिया है। जहां अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 46 फीसदी लोगों ने उधार लिया, वहीं 27 फीसदी लोगों ने ईएमआई का भुगतान करने के लिए उधारी का सहारा लिया। इनमें से 14 फीसदी लोगों को इसलिए कर्ज लेना पड़ा क्योंकि उन्होंने कोरोना के दौरान अपनी नौकरी खो दी।

शोध में यह भी सामने आया कि 2019 में भी 46 फीसदी लोगों ने उधार लिया था। इनमें से 33 फीसदी लोगों ने अपनी जीवनशैली के स्तर में सुधार के लिए कर्ज लिया, जबकि अन्य ने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने को उधार लिया था। *(रा.प., 04.11.20)*

भ्रष्टाचार में हम नंबर वन

टांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट 'ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर फॉर एशिया' के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में भारत अब पूरे एशिया में पहले नंबर पर है। इस रिपोर्ट की मानें तो करीब 50 फीसदी लोगों को अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। इनमें से 63 फीसदी ने इस डर से शिकायत भी नहीं की कि इससे उन्हें बाद में परेशानी न हो।

हमारे यहां सबसे शक्तिशाली समूह राजनीतिज्ञों का है। भ्रष्टाचार की बीमारी को दूर करने का काम केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति से हो सकता है। फिर राजनीतिक सिस्टम इसमें पहल क्यो नहीं करता?

क्योंकि, भारत में नेता सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। रिपोर्ट के अनुसार 72 फीसदी लोगों का मानना है कि भारत में नेताओं व सरकार में भ्रष्टाचार की समस्या काफी गंभीर है। करीब 46 फीसदी लोगों का मानना है कि अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में संलग्न रहते हैं। वहीं करीब 41 फीसदी लोगों ने कहा है कि अधिकांश सरकारी कर्मचारी और अफसर भ्रष्टाचार में संलग्न है। करीब 20 फीसदी लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार में न्यायाधीश सबसे कम सलंग्न रहते हैं। वहीं आम लोगों द्वारा पुलिस पर सबसे कम भरोसा जताया गया है।

(दै.भा., 13.12.20)

भ्रष्टाचार का वंशवाद बड़ी चुनौती: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सतर्कता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश में भ्रष्टाचार का वंशवाद बड़ी चुनौती है। यह राजनीतिक परंपरा बनता जा रहा है।

कार्यक्रम में मोदी ने कहा ''आज मैं आपके सामने एक बड़ी चुनौती का जिक्र करने जा रहा हूं। ये चुनौती बीते दशकों में धीरे-धीरे बढ़ते हुए अब देश के सामने एक विकराल रूप ले चुकी है। ये चुनौती है-भ्रष्टाचार का वंशवाद। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ भ्रष्टाचार। बीते दशकों में देश में देखा गया है कि जब भ्रष्टाचार करने वाली एक पीढ़ी को उचित सजा नहीं मिलती तो दूसरी पीढ़ी और ज्यादा ताकत के साथ भ्रष्टाचार करती है। कई राज्यों में ये राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बन गया है। भ्रष्टाचार का वंशवाद, देश को दीमक की तरह खोखला कर देता है।'' *(दै.भा., 28.10.20)*

प्रदेश में सीबीआई कार्रवाई पर रोक

राजस्थान में फोन टेपिंग से उठे सियासी तूफान के बाद से गहलोत सरकार ने यहां सीबीआई द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई या जांच करने पर रोक लगा दी थी। सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस लेने के बाद से जांच एजेंसी यहां न तो मामला दर्ज कर पा रही है और ना ही केंद्रीय विभागों में तैनात भ्रष्ट अफसरों को ट्रैप कर पा रही है। ऐसे में प्रदेश में तैनात केंद्रीय विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है।

इसकी बानगी यही है कि 20 दिन के भीतर एसीबी ने केंद्रीय विभागों के 9 अफसरों को घूस लेते गिरफ्तार किया है। ऐसा पहली बार है जब 20 दिन में केंद्रीय विभागों के इतने अफसरों को ट्रैप किया गया हो। *(दै.भा., 24.11.20)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
जयपुर	जी.एस. चाहर अशोक कुमार वर्मा	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी)	1,26,000	*रा.प., 18.10.20*
कोटा	पंकज गोयल	सहायक महानिदेशक, यूआइडीएआइ, नई दिल्ली	1,00,000	*रा.प. एवं दै.भा., 21.10.20*
जयपुर	नरेश चंद मीणा राजेश सिहाग	कांस्टेबल, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर थानेदार, जवाहर नगर थाना, श्रीगंगानगर	10,00,000	*रा.प. एवं दै.भा., 28.10.20*
जयपुर	जितेन्द्र कुमार शर्मा	अधिशासी अभियंता, जलदाय विभाग	50,000	*रा.प. एवं दै.भा., 13.11.20*
झुंझुनू	अनिल चौधरी	ईओ, नगर पालिका, चिड़ावा	3,00,000	*रा.प. एवं दै.भा., 14.11.20*
जयपुर	शेर सिंह चौधरी गोविंद अग्रवाल	एक्सईएन, नगर निगम हेरिटेज, जयपुर ठेकेदार (रिश्वत देने वाला)	1,00,000	*रा.प. एवं दै.भा., 14.11.20*
बाड़मेर	प्रेमाराम परमार नजीर खान	सेवानिवृत्त वरिष्ठ आरएएस अधिकारी दलाल	5,00,000	*रा.प. एवं दै.भा., 22.11.20*
बारां	महावीर नागर इन्द्रसिंह राव	जिला कलक्टर इन्द्रसिंह राव के पीए जिला कलक्टर, (भूमिका की जांच जारी है।)	1,40,000	*रा.प. एवं दै.भा., 10.12.20*
भीलवाड़ा	भगवत सिंह चौधरी	सहायक लेखाधिकारी, रजिस्ट्रार कार्यालय	51,000	*रा.प. एवं दै.भा., 17.12.20*

सतत् विकास लक्ष्यों की योजना

हम दुनिया का कायाकल्प करने की दहलीज पर खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत् विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक सम्पन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जाएगा।

गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य, बुनियादी सुविधाएं, उद्योग एवं नवाचार, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर, उपभोग व उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक प्रणालियां, शांति एवं न्याय और भागीदारी।

तेजी से आगे बढ़ रहा है राजस्थान

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान कुपोषण दूर कर सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सराहना पूरे देश में होती है।

कोरोना संकट के समय राजस्थान सतर्क है तथा 'कोई भूखा न सोए' हमारा मूल मंत्र रहा है। बच्चे देश का भविष्य हैं, वे स्वस्थ होंगे तो देश समृद्ध बनेगा। सरकार खाद्य सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी प्रतिबद्धता के साथ निभा रही है। उन्होंने राजस्थान सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू. एफ.पी.) के बीच हुए एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

(दै.भा., 30.10.20)

सांसों को सुकून: कार्बन उत्सर्जन कम

सूरज से मिल रही बिजली (सौर ऊर्जा) का बड़ा असर प्रकृति पर साफ नजर आ रहा है। राजस्थान में 5552 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्लांट है। इनसे प्रदेश में हर दिन करीब 2.5 करोड़ यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इससे 20.5 लाख किलो कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। यह करीब एक लाख पेड़ लगाने के समान है।

परंपरागत संयंत्र से बिजली उत्पादन न केवल महंगा है, बल्कि इससे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ कॉर्बनडाइ ऑक्साइड, सल्फर, कॉर्बन मोनो ऑक्साइड सहित अन्य गैस भी निकलती है, जो पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन होने से हमारी आब-ओ-हवा साफ हो रही है। यह सकारात्मक स्थिति सामने आने के बाद से अब ज्यादा से ज्यादा सोलर प्लांट, पैनल लगाने की जरूरत मानी जा रही है। इसके लिए गुजरात की तर्ज पर यहां सरकार की सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार के स्तर पर भी ज्यादा सहूलियत मिले तो बात बने। *(रा.प., 23.12.20)*

गरीबी रेखा कम करने के होंगे प्रयास

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) जोधपुर देश के गांवों में रहने वाले गरीबों की मूलभूत समस्याओं पर काम करेगा। आइआइटी के शिक्षक अपनी विभिन्न तकनीकी मदद से गांव में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के साथ गांव में ही विकास का नया खाका खीचेंगे। इस दौरान लोकतंत्र व विकेंद्रीकरण को बढ़ाने और गरीबी रेखा को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की नई तकनीक विकसित की जाएगी।

आइआइटी जोधपुर और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित देश के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायतीराज संस्थान ने हाल ही में एक एमओयू किया है। इसके अंतर्गत दोनों ही संस्थान आपस में मिलकर प्रोजेक्ट बनाएंगे और उन पर कार्य करेंगे। *(रा.प., 11.11.20)*

गरीबी स्तर से नीचे जाने का डर

कोरोना महामारी के चलते देश में करीब 40 करोड़ आबादी के गरीबी स्तर से नीचे जाने का डर है। पिछले दिनों नीति आयोग ने स्थिति में सुधार के लिए मंत्रालयिक स्तर पर बैठक रखी थी, जिसमें यूएनडीपी की भी मौजूदगी रही। इस बैठक में गरीबी को देश में कम करने और इसके लिए वैकल्पिक सुधार पर भी चर्चा की गई।

गौरतलब है कि नीति आयोग देश में गरीबी मापने के लिए खुद का पॉवर्टी इंडेक्स बनाने जा रहा है। इसका उद्देश्य जीएमपीआई के साथ मिलकर राज्यों में गरीबी कम करना है। पॉवर्टी इंडेक्स का लक्ष्य देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन-सहन के स्तर को बेहतर करना है।

(रा.प., 21.10.20)

पृथ्वी को है रिपेयर की जरूरत

जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि क्लाइमेट माइग्रेशन के कारण इस सदी के अंत तक लगभग 18 करोड़ से भी अधिक लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। हमें अब यह मानना होगा कि हम प्रकृति से बहुत ज्यादा ले चुके हैं। महत्वाकांक्षी लोगों की चाहत की कीमत हम सभी को चुकानी होगी।

अगर हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी हमें बचा लेगी। यह केवल हमारा दंभ कहलाएगा। यकीन मानिए अब पृथ्वी को रिपेयर की जरूरत है। हमें स्वीकार करना होगा क्लाइमेट माइग्रेशन शुरू हो चुका है। हमें प्रकृति के अधिकार का सम्मान करना होगा। *(दै.भा., 16.12.20)*

सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के प्रयास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात'कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करते हुए कहा कि 'देश के घर-घर में इन दिनों 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' का मंत्र गूंज रहा है। लोग देश में बने उत्पादों की मांग कर रहे हैं। युवा उद्यमी, स्टार्टअप इस मांग को पूरा कर सकते हैं। वे आगे आएं और पहल करे कि दुनिया में सबसे अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद भारत में बनें'।

उन्होंने कहा कि देश को सिंगल यूज (एक बार उपयोग होने वाला) प्लास्टिक से मुक्त करना ही है। यह भी 2021 के संकल्पों में से एक है। हमें यह संकल्प भी लेना चाहिए कि हम कचरा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हर नागरिक को इन संकल्पों को पूरा करना है।

(दै.भा., 28.12.20)

अभूतपूर्व होगा बजट-वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वादा किया है कि सरकार महामारी से पीड़ित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए तत्पर है। वर्ष 2021-22 का आम बजट संसद में एक फरवरी को पेश किया जाना है। बजट में बुनियादी ढांचे के लिए अधिक वित्त मुहैया कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए उन क्षेत्रों के लिए समर्थन बढ़ाना होगा जो कोविड-19 महामारी के चलते बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुसंधान और विकास में निवेश तथा टेलीमेडिसिन के लिए व्यापक कौशल का विकास महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है।

इसके साथ आजीविका संबंधी चुनौतियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के नए परिपेक्ष में देखना होगा। सीतारमण ने कहा कि भारत में 100 वर्षों में ऐसा बजट नहीं देखा गया होगा, जैसा इस बार महामारी के बाद आएगा। *(रा.प., 20.12.20)*

शुरू हुई महंगे मसाले हींग की खेती

देश में पहली बार हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में किसानों ने हींग की खेती की शुरूआत की है। इससे वहां खेती के तरीकों में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। इस इलाके की ठंडी रेगिस्तानी परिस्थितियों में व्यापक पैमाने पर बंजर पड़ी जमीन का सदुपयोग करने के उद्देश्य से हींग की खेती को अपनाया है। इससे किसानों को अच्छा लाभ हो सकेगा।

यह सीएसआइआर के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी, पालमपुर के प्रयासों से संभव हो रहा है। हींग के बीज लाने के बाद कृषि तकनीक विकसित की गई और क्वारिंग गांव में एक किसान के खेत में हींग के पहले पौधे की रोपाई की। भारत अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से सालाना 740 करोड़ रुपए हींग के आयात पर खर्च करता है। *(रा.प., 21.10.20)*

आत्मनिर्भर भारत का दायरा व्यापक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 'हम आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत का अर्थ व दायरा व्यापक है। इसमें गहराई और ऊंचाई है।' उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत घर-रोजगार के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपए के एक और पैकेज की घोषणा को देशवासियों के लिए उठाया गया एक सकारात्मक कदम बताया।

इस पैकेज में 2 करोड़ तक का घर लेने पर आयकर में 20 प्रतिशत की छूट देने, एक हजार तक कर्मचारियों वाली कंपनियों में नए कर्मचारियों के अंशदान के दोनों हिस्से सरकार द्वारा देने, कोरोना वैक्सीन के लिए 900 करोड़ का प्रावधान, पीएम शहरी आवास योजना में 18 हजार करोड़ रुपए और पीएम गरीब कल्याण योजना में 10 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। *(दै.भा., 13.11.20)*

जैविक खेती के प्रति रुझान बढ़ा

कोरोना काल में राहत की खबर है कि किसानों का जैविक खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। अब खेतों में तैयार होने वाले जैविक उत्पादों की खरीद-फरोख्त भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो सकेगी।

इसके लिए प्रदेश में जैविक खेती करने वाले किसानों को राजस्थान राज्य जैविक उत्पाद व प्रमाणिकरण संस्था की ओर से जैविक प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। जिससे किसान अपने उत्पाद की दर, उपलब्ध मात्रा और उत्पाद तैयार करने की ऑनलाइन एंट्री कर सकेंगे। प्रदेश में कई किसान गुणवत्ता से भरे जैविक उत्पादों की खेती को विकल्प बना रहे हैं। *(रा.प., 08.12.20)*

मिल सकती है खाद सब्सिडी

किसानों को मंडी के बाहर फसल बेचने के लिए कृषि कानून बनाने के बाद केंद्र सरकार अब जल्द ही एक नया कदम उठा सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की सफलता को देखते हुए सरकार किसानों को खाद सब्सिडी देने का फैसला लेने पर विचार कर रही है।

मुख्य दर निर्धारण समूह कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएपीसी) ने इसके लिए केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि किसानों को हर साल पांच हजार रुपए सीधे खाते में उर्वरक सब्सिडी के देने चाहिए। हालांकि, प्रति हैक्टेयर पर कितनी सब्सिडी दी जाए, इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। फिलहाल सीएसीपी की ओर से औसतन प्रति किसान 5000 रुपए देने का सुझाव है। *(रा.प., 23.10.20)*

अमीर हुए और अमीर, गरीब और गरीब

कोरोना संकट के बावजूद देश में टॉप 100 अमीरों की संपत्ति एक साल पहले की तुलना में 14 फीसदी बढ़ गई है। उनकी संपत्ति में करीब 39 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। प्रोग्रेसिव थिंकटैंक-द इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 643 अरबपतियों की संपत्ति तीन गुना बढ़ी है।

वहीं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल तक 15 करोड़ से ज्यादा आबादी और गरीब हो जाएगी। वहीं कोरोना महामारी के दौरान दुनियाभर में करीब 2.7 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। *(रा.प., 12.10.20)*

हटेगी धुंध, खिलेगी आर्थिक विकास की धूप

अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी दिखेगी, निर्यात और रोजगार की स्थिति भी बेहतर होगी। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी सुधार के कदम उठाए गए हैं। इससे खेती में निवेश बढ़ेगा। भारत प्रमुख कृषि निर्यातक देश के रूप में उभरेगा। नीति आयोग रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर प्रयासरत है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि हमने कोरोना काल का ऐतिहासिक इस्तेमाल किया है। इससे नींव पड़ी है जो भारत के सुदृढ़ भविष्य को सुनिश्चित करेगी। लंबे समय से लटके श्रम सुधारों को अंजाम दिया गया । इससे कारोबारी सुगमता और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। छोटे और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वर्ष 2021 में रोजगार, कारोबार और बाजार को नई राह मिलेगी। इससे आर्थिक विकास की धूप खिलेगी। *(रा.प., 19.12.20)*

सौर ऊर्जा से चमकेगी सरहद

पाकिस्तान से सटी अन्तरराष्ट्रीय सीमा सौर ऊर्जा से रोशन होगी। सरहद के नजदीक सीमावर्ती इलाकों में बड़े अल्ट्रा मेगा रिन्यूअल एनर्जी पॉवर पार्क लगाने के केंद्र सरकार के मसौदे पर राजस्थान में नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) से अलग-अलग अनुबंध होगा। यह राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और दोनों एजेंसियों के बीच अलग-अलग जॉइंट वेंचर होगा।

इन सोलर पार्क के जरिए सरहद तक भी सौर ऊर्जा पहुंचेगी। इसके लिए जैसलमेर में जमीन चिन्हित की गई है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह एवं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला के बीच बातचीत हुई है। सेना के अफसर भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। *(रा.प., 26.10.20)*

सोलर पावर प्लांट का बढ़ा ट्रेंड

सोलर पावर सिस्टम को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। बीते पांच सालों में घरों में सोलर पावर प्लांट लगवाने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। छत पर सोलर प्लांट लगवाकर जयपुर निवासी न सिर्फ बिजली के बिल को कम कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी नई दिशा दे रहे हैं।

आज से चार-पांच साल पहले तक इंडस्ट्री व ऑफिसेज में ही सोलर पावर पैनल लगते थे, लेकिन अब घरों में भी पैनल लगने का सिलसिला पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। शहर में 3750 सोलर कनेक्शन सुविधा का लाभ ले रहे हैं। घरेलू उपभोग के बाद शेष बिजली 3.14 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से डिस्कॉम को बेच मुनाफा भी उठा रहे हैं।

(दै.भा., 11.12.20 एवं रा.प., 14.12.20)

बिजली चोरी पकड़ने को सख्त चैकिंग

प्रदेश में अब शहर व गांवों में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए विजिलेंस चैकिंग कर वीसीआर भरी जाएंगी। जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम की टीमों को फील्ड में जाकर लोड चैकिंग व बिजली चोरी पकड़ने के लिए कहा गया है। ताकि मार्च से पहले 15 फीसदी बिजली छीजत का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व ऊर्जा सचिव के निर्देश के बाद जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम ने जून से विजिलेंस चैकिंग शुरू की। साढ़े तीन महीने में इंजीनियरों ने एक लाख 57 हजार जगह चैकिंग की। इनमें से एक लाख 20 हजार जगह बिजली चोरी पकड़ी। इस पर 285 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।

(दै.भा., 12.12.20)

सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वालों को छूट

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने अक्षय ऊर्जा के विनियम जारी किए हैं। विनियम में अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के कनेक्टिविटी चार्ज अब ढाई लाख रुपए प्रति मेगावाट किए गए हैं। विद्युत वाहनों के चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को 10 साल के लिए ओपन एक्सेस से सौर ऊर्जा संयंत्रों को 100 फीसदी छूट दी गई है।

इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में बड़े स्तर पर इजाफा होने की उम्मीद है। आयोग के सचिव बी.के. दोसी ने बताया कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार नई तकनीक आती रहती है। आयोग ने विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों के मानदंडों को इनमें शामिल किया है। *(रा.प., 03.11.20)*

उड़ा रहे हैं बिजली कंपनियों का फ्यूज

सरकारी महकमों के बकाया बिजली बिलों ने बिजली कंपनियों के फ्यूज उड़ा दिए हैं। प्रदेश में बड़े सरकारी विभागों के दफ्तरों का बकाया बिल लगभग 1500 करोड़ रुपए पहुंच गया है। हालांकि, जनता की दिक्कतों को देखते हुए जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम कनेक्शनों पर कार्रवाई से बच रहा है, लेकिन इसी शिथिलता का फायदा उठाकर सरकारी अधिकारी बिजली बिल चुकाने के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे।

इससे साल दर साल बकाया राशि में बढ़ोतरी होती जा रही है। जनवरी 2020 तक जहां करीब 1200 करोड़ बकाया था वहीं अब बढ़कर 1500 करोड़ रुपए हो गया है। सबसे ज्यादा बकाया नगर निगम और यूआईटी के 580 करोड़ और पीएचईडी का 390 करोड़ रुपए चल रहा है। *(रा.प., 16.10.20)*

आधा हो सकता है बिजली बिल

क्लाइमेट चेंज परफार्मेंस इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत अच्छे प्रदर्शन वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल है। ये देश गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन में कमी पर अच्छा काम कर रहे हैं। देश में रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता 5 साल में 226 प्रतिशत बढ़ी है। इससे 89 गीगावाट ऊर्जा मिल रही है।

सरकार का लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी को 450 गीगावाट करना है। वर्ष 2014 से 2020 के बीच सौर ऊर्जा भी साढ़े 13 गुना बढ़ गई है। देश में पिछले 5 सालों में क्लाइमेट इंडेक्स सुधार पर बहुत काम हुआ है। सोलर प्लांट की बिजली लगभग 2 रुपए प्रति यूनिट तथा थर्मल पावर प्लांट की बिजली की कीमत 4 रुपए प्रति यूनिट होती है। *(दै.भा., 14.12.20)*

शहर में लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर

जयपुर शहर में कुल करीब 2.51 लाख बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट पर 195 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। यह काम एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया है, जो एक साल में यह मीटर लगाएगी और पांच साल तक इनके मेंटीनेंस का काम भी देखेगी। यह केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। इसमें लागत का 60 फीसदी केंद्र सरकार व 40 फीसदी खर्चा राज्य की ओर से वहन किया जाएगा।

नए मीटर लगने के बाद उपभोक्ता अपने मोबाइल पर भी मीटर रीडिंग देख सकता है। इसके लिए उपभोक्ता को बिजली मित्र एप डाउनलोड करना होगा। कर्मचारियों को भी रीडिंग के लिए घर-घर मीटर तक नहीं जाना पड़ेगा। उपभोक्ता को प्री-पेड व पोस्ट-पेड दोनों तरह की सुविधा रहेगी। प्री-पेड में 15 फीसदी प्रति यूनिट की छूट भी मिलेगी।

(दै.भा., 08.11.20)

पानी की बर्बादी पर जुर्माना व जेल

अब पीने के पानी की बर्बादी या दुरुपयोग दंडनीय अपराध हो गया है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा इस संबंध में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। इसके अनुसार भूजल संसाधनों का दोहन कर निकाले गए पेयजल की बर्बादी पर अब पांच साल की जेल या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।

सीजीडब्ल्यूए के आदेशों के अनुसार जल बोर्ड, जल निगम, वाटर वर्कर्स डिपार्टमेंट, नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, पंचायत या किसी भी अन्य जो पेयजल सप्लाई संभालता है, यह सुनिश्चित करेंगे कि भूजल से मिलने वाले पेयजल की बर्बादी नहीं हो। इसके लिए एक सिस्टम विकसित करना होगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। *(दै.भा., 27.10.20)*

बिना अनुमति खोद सकेंगे ट्यूबवैल

राज्य में भूजल के हालात खराब होने के बावजूद राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में ट्यूबवैल खोदने के लिए अनुमति लेने की अनिवार्यता आखिरकार समाप्त कर दी है। केंद्र की गाइडलाइन के बाद राज्य में भूजल के हालात का परीक्षण किए बिना ही यह अनिवार्यता हटाने के आदेश जारी किए गए।

इसके तहत खेती, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू उपयोग, 10 घनमीटर प्रतिदिन से कम भूजल निकासी करने वाले सूक्ष्म व लघु उद्योगों, शहरी एवं ग्रामीण पेयजल योजना और सशस्त्र बल के प्रतिष्ठानों के लिए बिना स्वीकृति सीधे ट्यूबवैल खोदे जा सकेंगे। राज्य सरकार किसानों को ट्यूबवैल के लिए कृषि कनेक्शन भी देगी। *(रा.प., 08.12.20)*

पानी में बढ़ी फ्लोराइड की मात्रा

प्रदेश में राजधानी जयपुर समेत सभी 33 जिलों के पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा तय मानक से काफी ज्यादा है। नागौर जिले में तो पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक 90 पीपीएम (पार्ट पर मिलियन) के स्तर तक है, वहीं चूरू में 32 पीपीएम, श्रीगंगानगर में 28.2 पीपीएम और जयपुर में 28.1 पीपीएम के खतरनाक स्तर तक पाई गई है।

इतने ज्यादा स्तर वाला पानी पीने के योग्य नहीं होता है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने के कारण लोगों में हड्डियों, दांतों के कमजोर होने और घुटनों के जोड़ों में दर्द जैसी अनेक बीमारियां बढ़ रही है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा एक पीपीएम और डब्ल्यूएचओ के अनुसार अधिकतम सीमा 1.5 पीपीएम मानव जाति के लिए सुरक्षित मानी जाती है। *(रा.प. एवं दै.भा., 11.10.20)*

बोतलबंद पानी का उपयोग बढ़ा

राजस्थान में लोग हर महीने 5 करोड़ लीटर से ज्यादा बोतलबंद पानी (पैकेज्ड वाटर) पी रहे हैं। इसमें हर साल 10 से 12 फीसदी की बढ़ोतरी होती रही है। कोरोनाकाल में भले ही बोतलबंद पानी का कारोबार कम हुआ है, लेकिन इसके उलट स्थानीय लोगों में इसकी पहुंच 15 फीसदी तक बढ़ गई है।

स्वास्थ्य के प्रति चिंतित लोग ऑफिस, दुकान और शोरूम में पानी की छोटी बोतल का ही उपयोग करने लगे हैं। कई घरों में भी इसका उपयोग शुरू हो गया है। प्रदेश में कुल का 12 से 15 फीसदी बोतलबंद पानी हिमाचल प्रदेश और गुजरात से आ रहा है। यह अन्य राज्यों की तुलना में सस्ता है। इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भारतीय मानक ब्यूरो, केंद्रीय व राज्य भूजल विभाग के साथ ही जिला प्रशासन और फूड सेफ्टी विभाग की है। *(रा.प., 13.12.20)*

कागजों में होंगे 20 लाख कनेक्शन

प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष 20 लाख कनेक्शन कागजों में ही करने की तैयारी जलदाय अफसरों ने कर ली है। क्योंकि घर-घर पेयजल कनेक्शन के लिए सात संभागों में होने वाले सात हजार करोड़ रुपए के टेंडरों की प्रक्रिया इस वर्ष में पूरा होने की संभावना नहीं है।

दूसरी ओर विभाग ने इस वर्ष के लक्ष्य पूरे करने के लिए नया ही रास्ता खोज लिया है। अन्य योजनाओं में किए जा रहे जल कनेक्शनों को जल जीवन मिशन कनेक्शन के लक्ष्य में शामिल किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक महज 5 लाख कनेक्शन ही हुए हैं। कहा जा रहा है कि मिशन की टेंडर प्रकिया पर जलदाय मंत्री बी.डी. कल्ला और विभाग के तत्कालीन सचिव में विवाद के चलते मामला अटक गया था। *(रा.प., 01.12.20)*

पेयजल परियोजना को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर शहर के हवामहल, किशनपोल, आदर्शनगर और आमेर विधानसभा क्षेत्रों में बीसलपुर सिस्टम से बेहतर पेयजल व्यवस्था के लिए 165 करोड़ की परियोजना की घोषणा की है। परियोजना के लिए वित्त विभाग ने भी डेढ महीने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी। लेकिन परियोजना को धरातल पर उतरने के लिए जलदाय विभाग की वित्त समिति की बैठक का इंतजार है।

जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिस धीमी गति से परियोजना पर काम चल रहा है उस हिसाब से काम नए साल में ही शुरू हो सकेगा। *(रा.प., 01.11.20)*

जलाशयों को शुद्ध करेगा 'पिंजरा'

भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएससी) के वैज्ञानिकों ने अणुओं से पिंजरे जैसी एक ऐसी संरचना संश्लेषित की है जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी में घुलकर उसमें मौजूद रोगजनक बैक्टेरिया को मारने में सक्षम है। यह आणविक पिंजरा (पीएमबी 1) एक प्राकृतिक एंजाइम की तरह काम करता है। इस तकनीक से बड़े-बड़े तालाबों और जलाशयों का पानी शुद्ध किया जा सकेगा।

आइआइएससी में अकार्बनिक एवं भौतिक रसायन विभाग के शोधकर्ता सौमाल्या भट्टाचार्य ने बताया कि प्रकाश की उपस्थिति में यह आणविक पिंजरा प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जो बैक्टेरिया को खत्म कर देता है। जल शुद्धी व प्राकृतिक एंजाइम के तौर पर इसका व्यापक उपभोग होगा। प्रो. पार्थसारथी मुखर्जी व डॉ. मृगमय डे के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने यह महत्वपूर्ण शोध किया है। *(रा.प., 18.11.20)*

निवेश बना महिलाओं का मंत्र

कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में महिलाओं की रुचि शेयर बाजार की तरफ बढ़ी है। इस बीच महिलाओं ने गोल्ड बॉन्ड से लेकर म्यूचुअल फंड और एफ.डी. तक में निवेश किया है।

निवेश करने वाली महिलाओं में कामकाजी और गृहिणियां दोनों शामिल हैं। इनमें कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने पहली बार शेयर बाजार में निवेश किया हैं। ये महिलाएं अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। महिलाओं के खातों में पिछली तिमाही के मुकाबले इस साल अप्रेल से जून के बीच 32 प्रतिशत की बढ़त हुई है। इसमें शामिल 70 फीसदी महिलाओं ने शेयर बाजार में पहली बार निवेश किया है। इनमें करीब 35 फीसदी महिलाएं गृहिणियां हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें फायदा होता है। *(रा.प., 24.11.20)*

बच्चों में बढ़ा मोटापा व कुपोषण

कुपोषण से देश में बच्चों के बीमारू होने का खतरा मंडराने लगा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 20 राज्यों के बच्चों में मोटापा बढ़ा है तथा 16 राज्यों में कम वजन के बच्चों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। शिशु व पांच साल से कम उम्र के बच्चों की लंबाई में भी कमी आई है।

इससे पहले 2015-16 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 की रिपोर्ट में देश के बच्चों में कुपोषण कम होने का खुलासा हुआ था। लेकिन करीब 5 साल बाद की स्थिति में सुधार के बजाय कई राज्यों में कुपोषण में वृद्धि हुई है। देश के 17 राज्यों में बच्चों में एनीमिया यानी खून की कमी पाई गई है।

(रा.प., 25.12.20)

जननी सुरक्षा योजना की नई गाइडलाइन

प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए कई सालों से चल रही जननी सुरक्षा योजना की नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके अनुसार अब न्यूनतम 50 पलंग क्षमता और 80 स्क्वायर फीट प्रति पलंग की उपस्थिति वाले अस्पतालों को ही इस योजना से संबद्ध किया जाएगा। यह ही नहीं अनुमति चाहने वाले अस्पतालों को पहले से आयुष्मान बीमा योजना से संबद्धता भी अनिवार्य होगी।

इससे प्रदेश में खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इस योजना से संबद्ध अस्पतालों की संख्या कम होने की आशंका है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत अस्पताल में प्रसव कराने पर प्रसूता को निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है। *(रा.प., 27.10.20)*

स्कूली बच्चों को 10 दिन बस्ते से छुट्टी

भारी बस्ते का बोझ ढो रहे स्कूली बच्चों को बड़ी राहत मिलने वाली है। नई शिक्षा नीति के तहत महीने में 10 दिन उन्हें बस्ता स्कूल नहीं लाना होगा। यह छूट पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगी। इस बाबत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नीति का अंतिम प्रारूप सभी राज्यों के शिक्षा सचिव को भेजा गया है। इसका पालन अनिवार्य है।

इसके मुताबिक इन दस दिन में छठी से आंठवीं कक्षा के बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी। राज्य इसके बारे में सुझाव भेज सकते हैं। पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों को क्लासवर्क के लिए एक व तीसरी से पांचवीं कक्षा के लिए दो नोटबुक और छठी से आठवीं के बच्चों को खुले कागजों की फाइल रखनी होगी। स्कूलों में मिड-डे-मील, पेयजल व्यवस्था और किताब बैंक रखना होगा।

(रा.प., 28.11.20)

बिना पगार ज्यादा काम करती हैं महिलाएं

राष्ट्रीय सांख्यिकी की समय उपयोग रिपोर्ट में पहली बार यह रोचक खुलासा किया गया है कि बिना पगार के महिलाएं रोजाना पांच से आठ घंटे घरेलू कामकाज में व्यतीत करती हैं। वें खाना बनाने, साफ-सफाई, कपड़े धोने, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई घरेलू कामकाज के अलावा सामाजिक कार्यों में भी पुरुषों के साथ बराबरी से शामिल होती हैं।

समाजशास्त्री डॉ. विभा सिंह ने कहा है कि पहली बार इसे स्वीकारा गया है। यह महिलाओं के योगदान को मान्यता देने की दिशा में पहला कदम है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि परिश्रम के आधार पर आय गणना में महिलाओं को शामिल किया जाए तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। *(रा.प., 01.10.20)*

महिलाएं नहीं ले पाती वित्तीय फैसले

देश में महिलाएं भले ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हों, मगर उनके वित्तीय निर्णय एकल नहीं होते हैं। करीब 66 प्रतिशत एकल महिलाएं वित्तीय निर्णय लेने में परिजनों पर निर्भर रहती हैं। करीब 28 प्रतिशत पिता पर तो 5 प्रतिशत मां पर निर्भर रहती हैं। शादीशुदा 69 फीसदी महिलाएं भी अपने वित्तीय निर्णय खुद नहीं लेतीं।

यह तथ्य देश की एक फाइनेंशियल प्लानिंग फर्म द्वारा जयपुर, इंदौर, पुणे, बेंगलूरु, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में कराए गए सर्वेक्षण से सामने आया है। महिला की वैवाहिक स्थिति और मातृत्व उसके वित्तीय निर्णय लेने की स्थिति को प्रभावित करते हैं। सिर्फ 24 फीसदी महिलाएं ही खुद वित्तीय फैसले लेती है। *(रा.प., 11.12.20)*

दोगुनी हुई 'सिर्फ बेटी' की ख्वाहिश

देश में बीते कुछ अरसे में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। इनमें सबसे अहम भारतीय परिवारों में बेटे की चाहत में गिरावट आना है। अब न ज्यादातर परिवारों में हर कीमत पर बेटे की पैदाइश की जिद है और न ही ख्वाहिश।

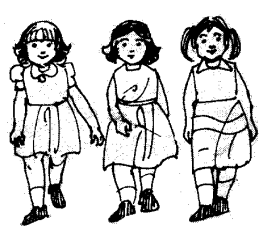

इंटरनेशनल इंस्टट्यूट ऑफ पॉपूलेशन साइंसेज के शोध के नतीजों से समाज के भीतर आए इस बुनियादी बदलाव का संकेत मिला है। इस बाबत किए गए सर्वे के अध्ययन से पता चला है कि दो बेटियों और बिना बेटे के 33.6 प्रतिशत घरों में परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाया गया या परिवार को इतना ही सीमित रखने का संकल्प लिया। तीन दशक के इस शोध में अहम निष्कर्ष यह है कि सिर्फ बेटियों वाले परिवार उच्च शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न हैं। लेकिन अभी भी ऐसे परिवारों की संख्या ज्यादा है जिनकी एक बेटा पाने की आस है और वे परिवार नियोजन का स्थाई रास्ता अपनाने को तैयार नहीं हैं। *(दै.भा., 12.10.20)*

सड़क सुरक्षा–जीवन रक्षा पर ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला आयोजित

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी 'कट्स' द्वारा सड़क सुरक्षा पर प्रमुख शक्तिपीठ मरमी माता धर्मशाला में पंचायत समिति स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पंचायत समिति प्रधान दिनेश बुनकर ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में स्वयं जागरूक होकर, यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की आदत का विकास करना चाहिए। इससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए युवा पीढ़ी में यातायात नियमों के बारे में जानकारी देकर जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता जताई।

इस अवसर पर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वित्तीय साक्षरता समन्वयक अरविंद पुरोहित ने कहा कि दुर्घटना कह कर घटित नहीं होती। इसलिए समय रहते बीमा अवश्य करवाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा एवं जीवन ज्योति सुक्ष्म बीमा योजना के बारे मे विस्तार से बताया। पाहुंना पुलिस चौकी के संजय सैनी ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 की जानकारी देते हुए बताया कि यातायात नियमों की पालना नहीं करने पर चालान काटा जाता है। इसका मकसद लोगों में जागरूकता लाना है।

कार्यशाला में 'कट्स' जयपुर के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में अवगत कराते हुए प्रशासन से ब्लॉक स्तरीय यातायात समितियों का गठन करवाने के लिए अनुरोध किया। कार्यक्रम का संचालन 'कट्स' मानव विकास केंद्र चित्तौड़गढ़ के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी मदनगिरी गोस्वामी ने किया। कार्यशाला में राशमी क्षेत्र के करीब 50 लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करें

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करना हर व्यक्ति का फर्ज बनता है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले से कोई पूछताछ नहीं की जाती बल्कि उन्हें अब पुरस्कृत किया जाता है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने की कवायद के तहत सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस तरह की गाइडलाइन जारी की है।

इसके अनुसार घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले सहायता मित्रों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। यह ही नहीं अस्पताल प्रशासन भी उनसे किसी तरह की पूछताछ नहीं करेगा और उन्हें अस्पताल से जाने की भी अनुमति बिना किसी झंझट के दी जाएगी। उधर परिवहन विभाग ने राजस्थान में घायलों की मदद करने वालों को पुरस्कार दिए जाने का भी प्रावधान कर दिया है। *(दै.भा., 05.10.20)*

सड़क दुर्घटनाओं में एक पायदान ऊपर

परिवहन मंत्रालय ने 2019 में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े जारी किए हैं। जिसमें देश में सड़क दुर्घटनाओं में मौत के मामले में राजस्थान एक पायदान ऊपर आया है। वहीं प्रदेश में साल 2018 की तुलना में 2019 में दुर्घटनाएं और मौतों की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 8 फीसदी और मृत्यु में 2.35 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

इससे राजस्थान देश में पांचवें पायदान से छठे पायदान पर आ गया था लेकिन सुधार होने की बजाय यह फिर से पांचवें पायदान पर आ गया है। वर्ष 2019 में मरने वालों की संख्या में 243 की बढ़ोतरी दर्ज की है। प्रदेश में 2019 में 23480 सड़क दुर्घटनाओं में 10563 लोगों की जान गई। गौरतलब यह है कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ होने के बावजूद हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले चार साल से इस क्षेत्र में कार्य करने वाली अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं को पर्याप्त बजट तक नहीं दिया गया। *(रा.प., 14.12.20)*

सड़क हादसों की स्थिति भयावह

प्रदेश में सड़क हादसों की स्थिति भयावह होती जा रही है। औसतन हर रोज 29 लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहे हैं। इससे निपटने केलिए यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं जिलों में गत तीन वर्षों के दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र (ब्लैक स्पॉट) चिन्हित किए हैं। भविष्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस ने संबंधित विभागों से कई सिफारिशें की है।

लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर, स्टेट हाईवे पर या शहर में गति सीमा से चले तो सड़क हादसे टाले जा सकते हैं। रोड़ इंजीनियरिंग की समस्या होने पर भी गति सीमा का पालन कर दुर्घटना टाली जा सकती है। यह कहना है स्मिता श्रीवास्तव, एडीजी ट्रैफिक का। उन्होंने बताया कि पुलिस समय-समय पर ब्लैक स्पॉट पर बैरिकेडिंग लगा कर ब्लैक स्पॉट का निवारण करती है। सड़क दुर्घटनाओं के लिए जनभागीदारी का होना बहुत जरूरी है। *(रा.प., 02.11.20)*

जानलेवा हाईवे जिम्मेदार कौन?

एक ओर पूरे देश में एक्सप्रेस हाईवे का जाल बुना जा रहा है और दुनिया की बेहतरीन सड़कें हमारे पास होने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर हम सड़क हादसों में मौतों के मामले में दुनिया के शीर्ष पर क्यों हैं? देश में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौत वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं।

देश में हो रही इन दुर्घटनाओं और मौतों के मामले में जिम्मेदार कौन है, सिस्टम या फिर हम खुद। क्योंकि, सबसे ज्यादा मौतें ओवर स्पीड से होती हैं। इसमें भी मरने वालों में युवाओं की संख्या ज्यादा है। कुल मिलाकर बेहतरीन सड़कों पर जोश के साथ होश की सबसे ज्यादा जरूरत है। वर्ल्ड रोड़ स्टेटिक्स 2018 की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान पत्रिका द्वारा बताया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में अमेरीका, जापान आगे है, लेकिन जान गंवाने में हम शीर्ष पर हैं। इसकी मुख्य वजह ओवर स्पीड और बिना हेलमेट के वाहन चलाना है। *(रा.प., 15.12.20)*

उपभोक्ता समाचार

उपभोक्ता फैसले

बैंक ने दस्तावेज खोए, देना होगा ढाई लाख का हर्जाना

जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच (जयपुर तृतीय) में शिव प्रसाद गुप्ता ने आईडीबीआई बैंक के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 में आईडीबीआई बैंक से मकान बनाने के लिए ऋण लिया था। इसके लिए प्लाट के मूल दस्तावेज बैंक के पास अमानत के तौर पर रखे थे। उन्होंने वर्ष 2011 में लिया गया पूरा ऋण ब्याज सहित अदा कर दिया। इस पर बैंक ने उन्हें नो-ड्यूज प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। बैंक से जब जमा कराए गए प्लाट के मूल दस्तावेज वापस मांगे तो बैंक अधिकारी टालमटोल करते रहे। अधिकारियों ने पहले तो दस्तावेज मुम्बई कार्यालय में होने की बात कही। बैंक में काफी चक्कर लगाने के बाद अधिकारियों ने दस्तावेज गुम हो जाना बताया। प्लाट के नए दस्तावेज बनवाने पर उन्हें अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी पड़ी। उन्होंने बैंक से खर्च की गई राशि मांगी तो बैंक प्रशासन ने देने से इनकार कर दिया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने गिरवी रखे दस्तावेज गुम करने को बैंक का सेवा दोष माना। मंच ने आईडीबीआई बैंक को आदेश दिए कि वह शिव प्रसाद गुप्ता को दो लाख पचास हजार रुपए बतौर हर्जाना अदा करे। साथ ही दस्तावेज गुम होने के कारण खर्च हुए 33 हजार रुपए भी उन्हें ब्याज सहित भुगतान करें।

(रा.प., 31.10.20)

बैंक से कैश निकासी व धोखाधड़ी पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का फैसला

हरियाणा के गुरुग्राम निवासी कैप्टन आंनद स्वरूप भारद्वाज ने दिल्ली में स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया था। उनके बैंक खाते से 2008 में 4 लाख 40 हजार रुपए किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर निकाल लिए थे। उन्होंने बैंक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक द्वारा उनके खाते से रुपए निकलने पर मैसेज ही नहीं भेजे। जिससे उन्हें पता नहीं लग सका कि उनके खाते से चोरी से पैसे निकाले जा रहे हैं। उपभोक्ता फोरम और उसके बाद राज्य उपभोक्ता फोरम ने भी सुनवाई के बाद उनकी याचिकाएं खारिज कर दी।

मामले को वह राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग तक ले गए। राष्ट्रीय आयोग ने भी उन्हें कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने अपना एनरोलमेंट मोबाइल बैंकिंग सेवा में नहीं कराया था, जिसकी वजह से बैंक द्वारा निकासी की सूचना नहीं दी गई। इसमें बैंक का कोई दोष नहीं है। मामले पर आयोग ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि मोबाइल बैंकिंग सेवा में एनरोल होना और बैंक एटीएम कार्ड व पिन की सुरक्षा करना ग्राहक की जिम्मेदारी है। इनके माध्यम से हुई अवैध निकासी के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(दै.भा., 22.11.20)

फ्लैट का पजेशन देने में देरी : कंज्यूमर कोर्ट दिलाएगा मुआवजा

होते रहते हैं ऐसे विवाद

रियल एस्टेट की हालत खस्ता होने की वजह से अब ग्राहकों और बिल्डर्स के बीच विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। फंसे प्रोजेक्ट में हजारों खरीददारों के करोड़ों रुपए अटके हुए हैं। कई बिल्डर समय से फ्लैट नहीं देते जिसकी वजह से ग्राहक ईएमआई के बोझ से भी मानसिक और आर्थिक रूप से काफी परेशान रहते हैं।

फ्लैट खरीददारों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब फ्लैट का पजेशन देने में देरी होने पर वे कंज्यूमर कोर्ट में भी मामला दर्ज कर सकते हैं और मुआवजा हासिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता अदालतों को इस मामले में आदेश देने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी उपभोक्ता अदालत किसी फ्लैट के पजेशन में देरी होने पर बिल्डर को मुआवजे का आदेश देने का हक रखती है। कोर्ट ने कहा कि यदि तय समय पर कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर पाता और फ्लैट का पजेशन समय से नहीं दे पाता तो उपभोक्ता द्वारा कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है और कंज्यूमर कोर्ट के पास इस मामले में आदेश देने और मुआवजा दिलाने का पूरा अधिकार है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने पिछले दिनों यह आदेश दिया था कि यदि पजेशन में देरी की वजह से किसी ग्राहक ने पूरी राशि वापस मांग ली हो, तो बिल्डर को यह कहने का अधिकार नहीं है कि ग्राहक का एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है और इस वजह से वह फ्लैट नहीं दे सकता।

(रा.प., 03.11.20)

कोरोना से बचाव का रखें पूरा ध्यान

प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी रोकथाम के लिए हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह मास्क पहनकर ही बाहर निकलें।

आदेशों के अनुसार मिलते समय दो गज की दूरी बनाएं रखें। सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूंके तथा भीड़भाड़ में जाने से बचें। मिलते समय हाथ मिलाने या गले लगने जैसे अभिवादन से बचा जाए। बार-बार साबुन व पानी से या सेनेटाइजर से हाथों को धोएं। कार्यस्थलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की जाए।

शादी समारोह या अंतिम संस्कार में निर्धारित संख्या में ही लोग शामिल हों। दुकानों व सार्वजनिक स्थानों पर बार-बार छूने वाली सतहों की सफाई व हैंड वॉश का पालन करें।

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259
फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्स: 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैरोबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)